ए-45011/4/2023-समन्वय II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को मई, 2023 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 2309-5054

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्यमंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (ईए) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी एंड सी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (जी 20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-II)/ओएमआई/क्रिप्टो आस्ति और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी)/संयुक्त सचिव (निवेश)/संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (वित्त मंत्री)/सभी सलाहकार/सीएएए

17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

18. गार्ड फाइल - 2023

ए-45011/4/2023-समन्वय.II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

विषय: मई, 2023 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

वृहद आर्थिक अवलोकन:

वैश्विक फैलाव के बीच, भारत की अर्थव्यवस्था ने अपने मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की त्वरित नीतिगत कार्रवाई के कारण वित्त वर्ष 2023 में अपनी विकास गति को बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है, और जो मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर वृद्धि से प्रेरित है।

जून 2022 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति में गिरावट शुरू हुई और मार्च 2023 में 1.3 प्रतिशत के निचले स्तर तक गिरती रही। अक्टूबर 2022 के बाद से गिरावट स्पष्ट प्रदर्शित हो रही है, विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति लगातार कम हो रही है तथा बहुत तेज गति से ईंधन और बिजली मुद्रास्फीति में भी गिरावट आ रही है।

वार्षिक आधार पर, वित्त वर्ष 23 में व्यापारिक निर्यात में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निर्यात में उच्च वृद्धि उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी नीतिगत पहलों के कारण हासिल की गई, जिसने वैश्विक निर्माताओं को अपना उत्पादन आधार भारत में अंतरित करने के लिए आकर्षित किया। भारत की बेहतर रिकवरी के कारण वित्त वर्ष 2023 में भारत के आयात में भी उछाल देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप गैर-तेल, गैर-सोना और चांदी के आयात में वर्ष-दर-वर्ष 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी छमाही में कम प्रभाव होने से पहले, वित्त वर्ष 2023 की पहली दो तिमाहियों में ऊर्जा की कीमतें भी ऊंची रहीं। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 23 में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 29.1 प्रतिशत बढ़ गया। इन विकासों के कारण, भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में जीडीपी के (-)8.5 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी छमाही में जीडीपी के (-)7.1 प्रतिशत पर आ गया।

राजकोषीय पक्ष पर, राजस्व वृद्धि द्वारा समर्थित व्यय को पुन: प्राथमिकता देने के सरकार के व्यावहारिक दृष्टिकोण ने वित्त वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बनाया। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में 6.7 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 6.4 प्रतिशत हो गया। इससे राजकोषीय समेकन के सरकार के संकल्प को अधिक बल मिलता है, क्योंकि इसका लक्ष्य वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है।

1. महत्वपूर्ण विकास:

(i) **माननीय वित्त मंत्री** ने निम्नलिखित **महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया:**

(क) कोरिया गणराज्य के इंचियोन में 2-5 मई, 2023 के दौरान निवेशक/द्विपक्षीय बैठकों और अन्य संबंधित बैठकों के साथ एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया।

(ख) माननीय वित्त मंत्री ने एफएसडीसी की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की और अन्य बातों के अलावा, अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतक और उनसे निपटने के लिए हमारी तत्परता, नियामक गुणवत्ता में सुधार करके वित्तीय क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने, भारत में कॉरपोरेट्स और परिवारों का ऋण स्तर, डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवाईसी ढांचे का सरलीकरण और सुव्यवस्थितीकरण, सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों के लिए निर्बाध अनुभव, बीमाकृत भारत-बीमा को अंतिम छोर तक ले जाने के लिए अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव, और आत्मनिर्भर भारत में रणनीतिक भूमिका निभाने के लिए जीआईएफटी आईएफएससी के लिए अंतर-नियामक मुद्दों को हल करने के संदर्भ में अपेक्षित समर्थन पर विचार-विमर्श किया। एफएसडीसी ने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी उप-समिति द्वारा किए गए क्रियाकलापों और एफएसडीसी के पिछले निर्णयों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी ध्यान दिया।

(ग) संधारणीय वित्त और जलवायु कार्रवाई के वित्तपोषण संबंधी सहयोग पर चर्चा करने के लिए यूरोपीय ग्रीन डील, यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री फ्रैंस टिमरमन्स के साथ द्विपक्षीय बैठक।

(ii) इस माह के दौरान निम्नलिखित **अधिसूचनाएं जारी की गईं:**

(क) ऑपरेशन शक्ति-राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 100/- रु. रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का।
(ख) नए संसद भवन के उद्घाटन के नए अवसर पर 75/- रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का
(ग) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) (संशोधन) नियम, 2023।

(iii) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित **महत्वपूर्ण बैठकें** आयोजित की गई/और इनमें भाग लिया गया:

(क) भारत-जर्मन वार्षिक परामर्श बैठक, 2023 नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग (केएफडब्ल्यू, जीआईजेड और आईकेआई) के तहत शामिल की जाने वाली नई परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की, ग्रीन और सस्टेनेबल विकास कार्यक्रम के तहत चल रहे पोर्टफोलियो और प्रगति की समीक्षा की।

(ख) 12वीं डीईए-एएफडी वार्षिक परामर्श बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें दोनों पक्षों ने 2023 के दौरान पोर्टफोलियो के आकार, नई परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित दर (उधार की शर्तें), पाइपलाइन के तहत और वर्तमान में कार्यान्वयन के अधिन परियोजनाओं के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए उदीयमान परियोजनाओं पर चर्चा की।

(ग) भारत सरकार-यूएसएआईडी साझेदारी समझौतों के तहत चल रही सात परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग और यूएसएआईडी के बीच वार्षिक त्रि-पक्षीय समीक्षा बैठक आभासी रूप में आयोजित की गई थी।

(घ) आईडीईएएस के तहत सभी क्रेडिट लाइनों की द्विवार्षिक संयुक्त पोर्टफोलियो समीक्षा 16-17 मई, 2023 के दौरान नई दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग और विदेश मंत्रालय की सह-अध्यक्षता में की गई थी।

(ङ) 31 मई, 2023 को बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तपोषण के प्रस्तावों पर विचार के लिए आर्थिक कार्य विभाग जांच समिति की 140वीं बैठक।

(च) 1-9 मई, 2023 के दौरान आईएमएफ मिशन टीम और भारत सरकार के विभिन्न विभागों और आरबीआई के बीच आईएमएफ अर्ध वार्षिक स्टाफ परामर्श आयोजित किया गया था।

(छ) भारत-स्विस द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) वार्ता वीसी के जरिए हुई।

(ज) भारत-रूस द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) वार्ता वीसी के माध्यम से आयोजित की गई।

(झ) श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा ऋण की मांग के अनुरोध पर चर्चा करने के लिए, भारत, जापान और फ्रांस की सह-अध्यक्षता में श्रीलंका के लिए ऋणदाता समिति की पहली बैठक 09 मई 2023 को आयोजित की गई थी।

(ञ) वर्ष 2023 के लिए एफएसबी कार्यक्रम और जी20 के लिए योजनाबद्ध डिलिवरेबल्स, एशिया को प्रभावित करने वाली कमजोरियों और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों, एशिया में एनबीएफआई की भूमिका और क्रिप्टो-आस्तियों पर चर्चा करने के लिए एफएसबी आरसीजी-एशिया बैठक आयोजित की गई थी।

(ट) आईएफएडी के कार्यकारी निदेशक मंडल ने अपने 138वें सत्र में हाइब्रिड माध्यमों से बैठक की जिसमें आईएफएडी के 2023 परिणाम-आधारित कार्य कार्यक्रम, नियमित और पूंजीगत बजट और 2024-25 के लिए मध्यम अवधि के कार्यनीतिक बजट दृष्टिकोण की अद्यतित स्थिति पर विचार किया गया; आईएफएडी के परिणाम-आधारित कार्य कार्यक्रम और 2023 के लिए बजट और 2024-25 के लिए सांकेतिक योजना का स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय; और एचआईपीसी और पीबीएएस की प्रगति रिपोर्ट, नीतियां और कार्यनीतियां, प्रतिबद्धता, के लिए उपलब्ध संसाधन शासन आदि।

(ठ) पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक (ईबीआरडी) की वार्षिक बैठक 16-18 मई, 2023 के दौरान आयोजित की गई थी।

(ड) अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) समूह की वार्षिक बैठक 22-26 मई, 2023 के दौरान आयोजित की गई थी।

(ढ) एनडीबी निदेशक मंडल (बीओडी) ने अपनी 40वीं बैठक और शासी मंडल (बीओजी) ने अपनी 8वीं वार्षिक बैठक में संघाई चीन में आयोजित की और निवेश चालन, वित्तीय कठिनाइयों, वैश्विक पूंजी बाजार में पहुंच जैसे नीतिगत मुद्दों सहित विभिन्न एजेंडे पर विचार किया। वैश्विक पूंजी बाजार, एनडीबी का सदस्यता विस्तार, पूंजी पर्याप्तता अवसंरचना, बैंक के वर्ष 2022 वार्षिक के वित्तीय खाते, 2022-26 के लिए सामान्य कार्यनीति का कार्यान्वयन आदि।

(ण) अवसंरचना वित्त सचिवालय ने इन्फ्रा फाइनेंसिंग, इन्फ्रा कार्यान्वयन और पीपीपी प्रोत्साहन के तहत मौजूदा आवश्यक पहल के माध्यम से अवसंरचना के विकास में प्रगति का पता लगाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव राज्यों के साथ भोपाल, मध्य प्रदेश में कार्यशाला आयोजित की।

(iv) भारत ने आईएमएफ के साथ **2020 द्विपक्षीय उधार व्यवस्था (बीबीए) के एक साल के विस्तार** के लिए आईएमएफ को सहमति व्यक्त की।

(v) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित **ऋण/अनुदान समझौतों** पर हस्ताक्षर/बातचीत की गई:

(क) "राजस्थान माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना-अतिरिक्त वित्तपोषण" के लिए ऋण वार्ता 18 मई, 2023 को आयोजित की गई थी।

(ख) आंध्र प्रेदश राज्य में तीन औद्योगिक क्लस्टर के लिए सड़क, जल आपूर्ति प्रणाली और बिजली वितरण नेटवर्क जैसी उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक अवसंरचना के विकास में सहायता करने के लिए "विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम - श्रृंखला 2" परियोजना के लिए एडीबी के लिए 141.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए।

(vi) इस माह के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में निम्नलिखित **क्षमता निर्माण कार्यक्रम** आयोजित किए गए:

(क) आईएसबी हैदराबाद में 'अवसंरचना के विकास में डिजिटल रूपान्तरण' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ख) एसपीजेआईएमआर, दिल्ली में 'अग्रणी के रूप में स्वामित्व चालित परियोजना प्रबंधन' विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ग) एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(घ) आईआईएम लखनऊ में अवसंरचना परियोजना वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

3. न्यूनतम शासन, अधिकतम सुशासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	:	03
विभाग में स्वीकृति का इंतजार है	:	08